International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialresearchjournals.com
Volume 2; Issue 11; November 2016; Page No. 81-82

नक्सलवाद व उसके प्रभाव

डॉ0 सुनीला एक्का

सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र), शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ, भारत।

प्रस्तावना

वर्तमान् दौर में नक्सली हिंसा को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बढ़ती नक्सली हिंसा ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रश्नगत् बना दिया है। लाल गलियारे का विस्तार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और नक्सलियों का संजाल मजबूत हो रहा है। नक्सली गतिविधियॉ देश के 20 राज्यों के 223 जिलों में 2000 थाना क्षेत्रों में फैली हुई है: प्रमुख राज्य हैं :– आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और पश्चिम् बंगाल। देश के लगभग छठवें भाग पर नक्सली अपना मजबूत नियंत्रण जमा चुके हैं।

प्रारंभ में नक्सली आंदोलन का उद्देश्य गरीब कृषकों की समस्याओं को दूर करना और उनके समर्थन में स्थानीय स्तर पर भू–स्वामियों का संगठित विरोध करना था, लेकिन धीरे–धीरे चीनी नेताओं के दर्शन से प्रभावित होकर हिंसक संघर्ष पर उतर आये। पिछले कुछ वर्षों में नक्सली समस्या अपना भयंकरतम् स्वरूप में पहुॅच गई है, क्योंकि अब नक्सलवाद भटका हुआ आंदोलन है, इसने अपने लक्ष्यों को खो दिया है। आज यह संसाधनों को लूट रहा है। मासूम लोगों, नागरिकों के खूल की होली खेल रहा है। हमारे सुरक्षाबलों के जवानों को मौत के घाट उतार रहा है। कई क्षेत्रों में नक्सलियों की समानांतर सरकारें चल रही है, ये विदेशी सहायता प्राप्त कर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न है।

नक्सलवाद व उसके प्रभाव

- आदिवासियों, वंचितों, दलितों तथा किसानों के उत्थान के लिये शुरू हुई यह लड़ाई उन्हीं के विनाश का कारण बन चुकी है। जो क्षेत्र नक्सलवाद से अधिक प्रभावित है, वहॉ नक्सलियों की समानांतर सरकारें चल रही हैं, ये टैक्स वसूलते हैं, इनकी अदालतें लगती है, जिसमें फैसले सुनाये जाते हैं। इनकी तरफ से फरमान भी जारी किये जाते हैं, जिन्हें न मानने वालों को सजा–ए–मौत दी जाती है।
- वर्ष 1991 में शुरू हुये उदारीकरण के दौर में नक्सलवादियों के प्रभाव क्षेत्र में अधिक वृद्धि कर दी क्योंकि अनेक निजी कंपनियों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने की पहल की गई, नदी घाट परियोजनाओं के लिये अनेक बड़े–बड़े बांध बनाये गये, जिससे आदिवासियों का व्यापक पैमाने पर विस्थापन हुआ तथा जंगल में स्थानीय आदिवासियों के परम्परागत् अधिकारों की अवहेलना की गई। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला, जिसके कारण शिक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्यायें जैसे के तैसे बनी हुई है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार से खाद्यान्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित् नहीं की जा सकी। इनका प्रभाव नक्सली हिंसा के रूप में सामने आया एवं विशेष रूप से सुरक्षाबलों के जवानों और सरकारी मुलाजिमों को इसका निशाना बनाया गया।
- सरकारी आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर पैसा पानी की तरह बहा रही है, परन्तु विकास का लाभ लोगों तक पहुॅच नहीं पा रहा है। इन क्षेत्रों में पुलिस और नेताओं की विश्वसनीयता भी बहुत संदिग्ध है। कई क्षेत्रीय नेताओं ने चुनावी लाभ प्राप्त करने नक्सलवादियों से हॉथ मिला रखा है, तो वहीं पुलिस ने 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम पर आम आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों का सिलसिला जारी है। यह सभी बातें नक्सलियों के प्रचार तंत्र को बढ़ावा देने के लिये काफी मदद्गार साबित हो रहीं है।
- आदिवासी और गरीबों को आज नक्सल ईलाकों से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियॉ विकास के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में जमीन से खनिज संपदा निकालने की होड़ में है।

रोजगार, निर्धनता और नक्सलवाद से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। इसे ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livehood Mission – NRLM) के अंतर्गत 3 लाख युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, इसी प्रकार महिला स्वसहायता समूहों (SHGs) के मध्य लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु सार्वजनिक–निजी सहभागिता (PPP) पहल की शुरूआत की गई। नक्सली हिंसा का दमन पुलिस और सुरक्षाबलों के जरिये नहीं किया जा सकता, इसके लिये आवश्यकता यह है कि ऐसा विकास, जिसमें आदिवासियों, पिछड़े और वंचितों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित् हो और इन्हें यह कहीं न लगे कि इनके अधिकारों पर कोई अतिक्रमण कर

रहा है या इनके हकों पर कोई डाका डाला जा रहा है। नक्सली हिंसा पर यदि काबू ना पाया गया, तो यह हमारी आंतरिक सुरक्षा को खण्डित कर देगी। इससे अलगाववादी एवं विध्वंसकारी शक्तियों को बल मिल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी इसके प्रभाव में जर्जर होती है। इन सभी बातों का मिला–जुला प्रतिकूल प्रभाव विकास पर पड़ता है, विकास बाधित होता है, साथ ही वैश्विक मंच पर हमारी स्थिति कमजोर पड़ती है। इस स्थिति से निपटने के लिये यह आवश्यक है कि इस समस्या पर गंभीर मंथन कर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाये और इसके अनुरूप समस्या के उन्मूलन के लिये प्रयास किये जायें। विकासात्मक कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होंगे, इसके साथ–साथ इन क्षेत्रों से लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास तथा उनके प्रति लोगों की विश्वास बहाल करने का भी प्रयास किया जाना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. राजकिशोर / वनवासियों का संघर्ष, 1995 / वाणी प्रकाशन नई दिल्ली / पृष्ठ 10, 11
2. डॉ. टी.पी. त्रिपाठी / मानव अधिकार 2014 / इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस / पृष्ठ 128, 130